लुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियां

1226. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुचित सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कई जनजातियां लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं और मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में बसने वाली ऐसी ही एक जनजाति बिरहोर (बिरहूल) के व्यक्तियों की संख्या घट कर केवल 85 रह गई है ;

(ख) देश के अन्य कौन-कौन सी जनजातियों के लुप्त हो जाने की आशंका हैं ;

(ग) क्या निकोबार द्वीपसमूह की "शाम्पेन" जनजाति और मध्य प्रदेश की पहाड़ी "कोरबा" जनजाति भी उन जनजातियों में से है जिनके लुप्त होने की आशंका है ; और

(घ) सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति समुदाय जिनकी जनसंख्या अखिल भारतीय स्तर पर 1000 से कम है परन्तु 1971 की जनगणना की तुलना में जिनकी संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिखाए गए हैं। आदिवासी उपयोजना दृष्टिकोण के अधीन, पांचवीं पंचवर्षीय योजना से, अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत के महापंजीयक जनगणना संचालन की सूचना के अनुसार "बिरहोरे" जनजाति मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में नहीं रह रही है। ये आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश के रायगढ़, सुरगुजा तथा दुर्गा जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रह रही "बिरहोरे" जनजाती की 1961-1981 जनगणनाओं में जनसंख्या प्रवृत्ति इस प्रकार थी --

जनगणना अवधि	जनसंख्या
1961	513
1971	738
1981	561

(ग) और (घ) जी नहीं। निकोबार द्वीप समूह की शैम्पेन्ज जनजाति की जनसंख्या प्रवृत्ति 1961-1981 जनगणनाओं के दौरान इस प्रकार थी --

जनजाति का नाम	जनगणना की अवधि		
	1961	1971	1981
निकोबार द्वीप समूह की "शैम्पेन्ज" जनजाति	71	92	223

भारत के महापंजीयक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार "पहाड़ी कोरबा" मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वतंत्र रूप से अधिसूचित नहीं है। इसलिए उनकी जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्रलेखों में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य सरकार के अनुसार, पहाड़ी कोरबा की जो कि अनुसूचित जनजाति के मुख्य कोरबा समूह का एक भाग है, 1961-1981 जनगणना के दौरान जनसंख्या प्रवृत्ति इस प्रकार थी --

	जनसंख्या अवधि		
	1961	1971	1981
मध्य प्रदेश के पहाड़ी कोरबा	4000	13488	16860

विवरण

1971–1981 जनगणना के दौरान कम हो रही अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति का नाम	राज्य का नाम	जनसंख्या 1971	1981
मारवाड़	गुजरात	531	519
खम्बा	अरुणाचल प्रदेश	848	342
गोवा	अरुणाचल प्रदेश	703	625
कोटा	भारत	1291	720
	कर्नाटक	103	75
	केरल	—	41
	तमिलनाडु	1188	604
मेलायेकन्दी	भारत	543	199
	कर्नाटक	46	129
	तमिलनाडु	497	70
मलेरू	कर्नाटक	1321	966
ओंगे	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	112	97
योबिन	अरुणाचल प्रदेश	920	5
जखरिंग	अरुणाचल प्रदेश	23	14

Denial of cash allowance to cashiers of RRBS under SBI in some States

1227. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Regional Rural Banks sponsored by State Bank of India in Andhra Pradesh are allowing cash allowance to the cashiers as per rules operating in State Bank of India;

(b) if so, what are the reasons for not allowing the same in such banks sponsored by State Bank of India in other States; and

(c) whether Government have received the notice of agitational programme from the All India Regional Rulal Bank Employees Association; if so, what steps Government have taken to resolve this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Yes, Sir. The Government have received agitational notice from All India Regional Rural Bank employees Association. The employees of Regional Rural Banks have already been allowed pay scales etc. applicable to equated posts in sponsor banks w.e.f. 1.1.91. A working group created by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will consider the matter relating to promotion policy in RRBs, framing service regulations and also for considering any other matters affecting RRB employees.